HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

CRIMINAL REVISION No. - 4788 of 2024

Ram Khelawan

.....Revisionist(s)

Versus

State Of U.P. And 3 Others

.....Opposite Party(s)

Counsel for Revisionist(s)	:	Abhijeet Mukherji, Rajiv Lochan Dwivedi
Counsel for Opposite Party(s)	:	Ashwini Kumar Srivastava, G.A., Krishna Kant Bhatt

Court No. - 84

HON'BLE LAKSHMI KANT SHUKLA, J.

1. The matter is taken up out of turn being mention made in the morning by learned counsel for the revisionist after giving notice to learned counsel for O.P. No. 4 but no one has appeared on behalf of O.P. No. 4 to oppose the criminal revision.

2. Heard Mr. Abhijeet Mukherji, learned counsel for the revisionist, learned A.G.A. for the State and perused the record.

3. Learned counsel for the revisionist has submitted that the matter was referred for mediation to the Mediation and Conciliation Center of this Court where the parties have amicably resolved their dispute and a settlement agreement arrived at between the parties on 26.10.2026 (Copy of the same has been provided by learned counsel for the revisionist).

4. Paragraph No. 7 of the aforesaid settlement agreement is relevant in the matter. It is thus contended that in view of aforesaid settlement agreement, the present criminal revision may be allowed by this Court. Paragraph No. 7 of the settlement agreement dated 26.10.2026 is reproduced herein under:

> "7. वादकारियों के बीच में निम्नलिखित समझौता सम्पन्न हुआ है:-
> क. यह कि पक्षकारों के मध्य यह सहमति हुई हैं कि वे अलग-अलग रहेंगे तथा तलाक लेंगे इस सन्दर्भ में पक्षकार आज दिनांक 21.09.2026 से एक सप्ताह के मध्य आपसी सहमति से श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजीपुर के समक्ष हिंदू विवाह अधिनियम की

धारा 13-बी के अन्तर्गत एक विवाह विच्छेद याचिका दायर करेंगे तथा मध्यस्थता केन्द्र में नियत अग्रिम दिनांक 12.10.2026 को विवाह विच्छेद याचिका के प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करेंगे!

ख. यह कि दोनों पक्षों के बीच यह समझौता हुआ है कि राम खेलावन (पुनरीक्षणकर्ता-पति) विपक्षी सं. 4- पूनम देवी (पत्नी) को एकमुश्त धनराशि रु.25,00,000/- (रु. पचीस लाख मात्र) देगा, जिसमें पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता, स्त्रीधन तथा भरण-पोषण भी शामिल है। उपरोक्त राशि पति डिमाण्ड ड्राफ्ट के जरिये पत्नी को अदा करेगा।

ग. यह कि आज दिनांक 21.09.2026 को पति रु.8,50,000/- (रु. आठ लाख पचास हजार) एवं रू.8,50,000/- (रु. आठ लाख पचास हजार) का दो डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. 116357 दिनांकित 17.09.2026 एवं डिमाण्ड ड्राफ्ट सं. 116358 दिनांकित 17.09.2026 बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा Poonam (पत्नी) के नाम जारी किया गया है, मध्यस्थता केन्द्र में प्रस्तुत किया है, जो कि पत्रावली में रखा गया है। यह डिमाण्ड ड्राफ्ट पत्नी को मध्यस्थता केन्द्र में नियत अग्रिम तिथि 12.10.2026 को अंतिम समझौता के समय सौंप दिया जायेगा।

घ. यह कि बकाया राशि अर्थात् रु. 8,00,000/-(रू. आठ लाख मात्र) पति द्वारा पत्नी को श्रीमान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गाजीपुर के समक्ष विवाह विच्छेद याचिका (जो कि दाखिल किया जाना है) के अंतिम निर्णय के समय डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से अदा किया जायेगा।

ङ. यह कि पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस बीच की अवधि में वे एक-दूसरे या परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर लंबित मुकदमे (चाहे दीवानी हो या आपराधिक) को आगे नहीं बढ़ाएंगे।

दोनो पक्ष दिनांक 12.10.2026 को पुनः मध्यस्थता केन्द्र में उपस्थित होंगें।"

5. According to aforesaid settlement agreement, the parties have decided to live separate and revisionist shall pay Rs. twenty five lacs permanent alimony. Out of which Rs. 17 lacs has already been paid and rest part of permanent alimony i.e. Rs. Eight lacs is payable at the time of final disposal of matter before the Trial Court. In view of above, the present criminal revision may be allowed by this Court.

6. Per contra, learned A.G.A. has no objection to the same. No one is present on behalf of O.P. No. 4 to oppose the aforesaid submission.

7. In view of above, the present criminal revision is liable to be allowed in terms of aforesaid paragraph No. 7 of settlement agreement dated 26.10.2026.

8. Accordingly, the present criminal revision is **allowed.** The impugned order dated 16.03.2023 passed by J.M. 1st Class-cum-Civil Judge, J.D.(F.T.C.) Court No. 2, Ghazipur as well as order dated 06.07.2024 passed by learned Additional District & Sessions Judge/Special Judge, E.C.Act, Court No. 4, in Appeal No. 105 of 2023 is hereby set aside.

9. The mater is remitted to the Trial Court for deciding the matter in the light of settlement agreement arrived at between the parties.

(Lakshmi Kant Shukla,J.)

November 2, 2026
RPD

Digitally signed by :-
RATAN PRAKASH DWIVEDI
High Court of Judicature at Allahabad